ईरान की पहेली

लेखक- रमिन जहानबेगलो (प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

2 मई, 2019

"तेल को लेकर तेहरान के साथ वाशिंगटन के टकराव से शासन में बदलाव होने की संभावना नहीं है।"

अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर.पोम्पिओ ने हाल ही में घोषणा की कि ट्रम्प प्रशासन ग्रीस, इटली, भारत, जापान, चीन, तुर्की और दक्षिण कोरिया सहित आठ देशों को दी गई सभी छूटों को समाप्त कर रहा है, ताकि उन्हें ईरानी तेल से दूर किया जा सके और ईरानी तेल निर्यात को शून्य किया जा सके। जब ट्रम्प प्रशासन ने नवंबर में तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया था, तब अमेरिका ने इन देशों को ईरानी तेल आयात करने के लिए अस्थायी छूट दी थी।

मीडिया को संबोधित करते हुए पोम्पिओ ने कहा था, 'आज की घोषणा हमारे दबाव अभियान की पहले से ही महत्वपूर्ण सफलताओं पर आधारित है। हम ईरानी शासन पर अधिकतम दबाव लागू करना तब तक जारी रखेंगे, जब तक कि उसके नेता अपने विनाशकारी व्यवहार को नहीं बदलेंगे, ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे और वार्ता की मेज पर वापस नहीं लौटेंगे।" इस अभ्यास का लक्ष्य ईरानी कच्चे तेल के निर्यात को शून्य तक कम करना है और तेल निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा से वर्तमान ईरानी शासन को वंचित करना है।

हालांकि, अमेरिकियों के इस कदम से विश्व बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। कीमतों में पहले से ही वृद्धि होना शुरू हो गयी थी, जब अमेरिका ने ईरानी तेल खरीददारों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। वैश्विक स्तर पर एशिया में कच्चे तेल की कीमतों में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद ब्रेंट क्रूड वायदा बाजार 74 डॉलर प्रति बैरल से अधिक बढ़ गया था, लेकिन अक्टूबर के उच्च स्तर 86 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहा।

हालांकि, पोम्पिओ ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य ईरानी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करना है, लेकिन उन्होंने 'एम्बार्गो' (व्यापार रोक) शब्द का उल्लेख नहीं किया, जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा लागू किए जाने की आवश्यकता है और ईरानियों द्वारा युद्ध के रूप में व्याख्या की जा सकती है। इसलिए, ट्रम्प प्रशासन द्वारा उठाए गए नए कदम से ईरान से तेल की खरीद जारी रखने वाले देशों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने का खतरा बढ़ जाता है। चीन और भारत ईरानी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीददार हैं। मार्च तक, भारत, ईरान तेल की प्रतिदिन लगभग 2,58,000 बैरल की दैनिक खरीद के लिए प्रतिबंधित था।

चीन और जापान ने प्रतिदिन क्रमशः 6,13,000 और 1,08,000 बैरल ईरानी तेल का आयात किया। नतीजतन, विदेशी पूंजी के बिना, ईरान निर्यात के लिए अधिक तेल और गैस का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ईरान को एक कानूनी ढांचा भी चाहिए जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद् करेगा। इस बीच, ट्रम्प प्रशासन, ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक युद्ध को बढ़ाकर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC, आईआरजीसी) और उसके कुलीन वर्ग बल को कमजोर करने और आम ईरानी नागरिकों को इस्लामी शासन के खिलाफ करने की उम्मीद कर रहा है।

कुछ हफ्ते पहले, अमेरिका ने आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। यह पहली बार था जब अमेरिकी प्रशासन ने एक विदेशी सरकार की एक शाखा को आतंकवादी इकाई के रूप में चिह्नित किया हो। सऊदी अरब और इजरायल दोनों ने अमेरिकी कदम की सराहना की, लेकिन वाशिंगटन का कदम निश्चित रूप से इराक और लेबनान जैसे देशों को और भी कठिन परिस्थितियों में डाल देगा क्योंकि उनके पास आईआरजीसी की सैन्य और वित्तीय उपस्थिति से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आईआरजीसी को एक आतंकवादी संस्थान के रूप में नामित करने से अमेरिका को उन व्यक्तियों और फर्मों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिलती है, जिन्होंने आईआरजीसी को सामग्री सहायता प्रदान की है। एक बार फिर, इसमें यूरोपीय और एशियाई कंपनियां शामिल हैं, जो आईआरजीसी के सहयोगियों के साथ सौदा करती हैं।

इस बीच, अमेरिकी पहलों के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता की प्रतिक्रिया ने मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी को आईआरजीसी के प्रमुख के रूप में जनरल हुसैन सलामी के साथ बदल दिया है। सलामी को अमेरिका के खिलाफ अपनी गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। अपनी कई पीढ़ियों की तरह ही, वे भी 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान आईआरजीसी में शामिल हो गए और संस्थान के आंतरिक मामलों के प्रभारी के रूप में कई पदों पर रहे।

जैसा-कि ईरान और अमेरिका के बीच वैचारिक शत्रुता अपरिमेय आयाम ले रही है, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को फारस की खाड़ी क्षेत्र में तनाव और युद्ध के खतरों को कम करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। लेकिन ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के पहले से ही ईरान के प्रति अपनी शत्रुता प्रदर्शित करने के तरीकों से बाज नहीं आ रहे हैं और अयातुल्ला के शासन की कठोर प्रतिक्रियाओं ने पहले ही इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की फिर से चुनाव में मदद् की है।

ईरान के पास मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसकी मिलिशिया और इसके प्रतिनिधि अमेरिका या इजराइल से किसी भी सैन्य उकसावे की जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेबनानी हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के बीच एकजुटता तीन दशकों से अधिक समय तक रही है। इसके अलावा, ईरान के साथ हिजबुल्लाह के संबंध एक रणनीतिक साझेदारी है और अयातुल्ला और आईआरजीसी ने नसरल्लाह और कुछ अन्य वरिष्ठ हिजबुल्लाह अधिकारियों को इजराइल या अमेरिका के साथ अंतिम टकराव में विश्वसनीय सहयोगी माना है।

इसलिए, जैसा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी बयानबाजी बढ़ रही है, इसमें संदेह नहीं है कि अयातुल्ला के शासन के साथ ट्रम्प के टकराव के लिए सैन्य सीमाएं होंगी। तथ्य यह भी है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उन छूटों को खत्म किया गया जो इस्लामी गणतंत्र को प्रमुख सहयोगियों को तेल निर्यात करने की अनुमति देती थी। पोम्पिओ ने डलास होटल में ईरानी-अमेरिकी समुदाय के नेताओं के साथ एक बंद दरवाजे की बैठक में पुष्टि की कि ट्रम्प प्रशासन 'शासन परिवर्तन में तेजी लाने के लिए ईरान के अंदर अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करने जा रहा है।' ट्रम्प प्रशासन की ओर से यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दर्शाता है कि ईरान के खिलाफ दिखाई गई दुश्मनी के बावजूद, तेहरान में सैन्य शक्ति का प्रयोग कर के शासन को उखाड़ फेंकने का निर्णय कहीं से भी बुद्धिमानी साबित नहीं होगी।

GS World टीम...

अमेरिका-ईरान विवाद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि अमेरिका ईरानी सरकार पर दबाव बनाने के अभियान को प्रभावशाली ढंग से तेज करेगा और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान के नेता 'विनाशकारी व्यवहार' बदल नहीं लेते हैं, अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं करने लग जाते और बातचीत की मेज पर नहीं बैठ जाते।
- पोम्पिओ की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद आई है कि उनका प्रशासन ईरान से तेल आयात करने वाले देशों को अतिरिक्त 'महत्वपूर्ण कटौती अपवाद' जारी नहीं करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने पिछले वर्ष नवंबर में भारत और सात अन्य देशों को 180 दिनों की अवधि के लिये ईरान से तेल आयात में छूट दी थी, जो 2 मई को समाप्त हो गई है।
- भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- दुनिया में सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- ईरान ने अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018 के दौरान भारत को 18.4 मिलियन टन कच्चे तेल की आपूर्ति की है।
- फैसले से भारत समेत आठ देशों को आगामी दो मई तक ईरान से तेल के अपने आयात को नीचे लाना होगा। जबकि, ग्रीस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने पहले ही ईरान से अपने तेल आयात में भारी कमी कर दी है।

प्रतिबंध का प्रभाव

- ईरान के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल निर्यात है जो प्रतिबंध की वजह से संकट में आ जाएगा।
- वर्ष 2018 में वैश्विक तेल उत्पादन में ईरान का हिस्सा 4% था। ईरान पर प्रतिबंधों के पश्चात् वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
- आपूर्ति में व्यवधान की वजह से तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- दुनिया के तीन सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वे वैश्विक तेल बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- अमेरिका ने कहा है कि वह तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था या कंपनी पर वित्तीय अंकुश लगाएगा, जिसमें कंपनियों द्वारा स्विफ्ट बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध, उन कंपनियों की किसी भी अमेरिकी संपत्ति की जब्ती और डॉलर में लेन-देन जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत पर प्रभाव

- **रिफाइनरियों के लिये तेल की आपूर्ति:** अमेरिका के इस निर्णय से भारत पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- अमेरिका ने हाल ही में भारत के एक अन्य शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इन परिस्थितियों में अमेरिका का हालिया निर्णय भारत के लिये मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
- आयात बिल में वृद्धि से रुपए पर दबाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महँगाई बढ़ेगी।

ईरान द्वारा प्रदत्त भारत को विशेषाधिकार

- ईरान अन्य देशों को 30 दिन और भारत को 60 दिन की क्रेडिट सीमा देता है।
- ईरान ने भारत को सीधे रुपए में भुगतान करने की भी सुविधा प्रदान की थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुल राशि का 55% भुगतान यूरोपीय बैंकों में किया जाएगा तथा शेष 45% राशि का भुगतान भारत स्थित बैंक में किया जाएगा, जिसका उपयोग भारत से आयात के लिये किया जाएगा।
- इसके बाद, यूरोपीय बैंकों द्वारा भुगतान बंद किये जाने की स्थिति में ईरान ने भारत को 100% भुगतान रुपए में करने की सुविधा दी, यह व्यवस्था ईरान के साथ P 5+1 देशों की संधि होने तक जारी रही।
- पुन: 55% भुगतान यूरो और 45% रुपए में करने की व्यवस्था की गई।
- ईरान, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिये माल ढुलाई में भी छूट प्रदान करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन सऊदी अरब करता है।
2. ईरान अन्य देशों को 30 दिन और भारत को 60 दिन की क्रेडिट सीमा देता है।
3. ईरान ओपेक का संस्थापक सदस्य है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

1. Consider the following statements-

1. Saudi Arab produces most energy in the world.
2. Iran provides India 60 days credit limit and others, of 30 days.
3. Iran is the founding member of OPEC.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- हाल ही में ईरान और अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव ने भारत के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर दी है। इससे निपटने के लिए भारत को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. The increasing tension between Iran and America has created tension infront of India. What strategy should India adopt to tackle this? Discuss. (250 Words)

नोट : 1 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।